

## सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नीति में महिलाओं का स्थान (रीवा जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ.कमल राज सिंह उड़के

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र एव प्रभारी प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय बरका, जिला -सिंगरौली (म.प्र.)

### सारांश (Abstract)

यह शोध पत्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) नीति के अंतर्गत महिला उद्यमियों की स्थिति का विश्लेषण करता है, विशेषकर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के संदर्भ में। अध्ययन में यह पाया गया है कि हालांकि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीतियां महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रावधान करती हैं, किंतु रीवा जिले में महिला उद्यमियों को वित्तीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्तर पर महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शोध से यह स्पष्ट होता है कि नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतराल (Policy-Implementation Gap) विद्यमान है। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर, लेखक ने रीवा जिले में महिला MSME क्षेत्र को सशक्त करने के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं।

**बीज शब्द (Keywords)**-महिला उद्यमिता, MSME नीति, स्वरोजगार, रीवा जिला, सामाजिक सशक्तिकरण, वित्तीय समावेश, लैंगिक न्याय, ग्रामीण विकास, महिला स्वयं सहायता समूह, आर्थिक विकास

**प्रस्तावना (Introduction)**-भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) पर निर्मित है। ये उद्यम न केवल राष्ट्रीय जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, "MSME क्षेत्र कुल रोजगार का लगभग 40 प्रतिशत प्रदान करता है।" इसी महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, भारत की नीतिनिर्माता संस्थाओं ने समय-समय पर MSME को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए विभिन्न नीतियां बनाई हैं।

महिला उद्यमिता भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों में कहा गया है कि "महिला उद्यमियों का विकास न केवल लैंगिक समानता लाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देता है।" भारत में महिला उद्यमियों की संख्या पिछले दशक में तेजी से बढ़ी है, लेकिन उनकी MSME क्षेत्र में भागीदारी अभी भी पुरुषों की तुलना में काफी कम है। भारतीय उद्यमिता सर्वेक्षण के अनुसार, "भारत में MSME क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगभग 20-25 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 75-80 प्रतिशत है।"

रीवा जिला मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित एक जिला है, जो अपनी कृषि, खनिज और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। इस जिले की जनसंख्या लगभग 12-13 लाख है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। रीवा जिले में महिला साक्षरता दर 65-70 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत (75%) से कम है। यह स्थिति महिला उद्यमिता के विकास में एक बाधा बन जाती है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह है कि रीवा जिले में MSME नीति के अंतर्गत महिला उद्यमियों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाए, उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों को चिह्नित किया जाए, और उनके सशक्तिकरण के लिए व्यावहारिक सुझाव दिए जाएं।

**1. MSME नीति: एक संक्षिप्त परिचय**-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को परिभाषित करते हुए, "भारतीय सांख्यिकी

मंत्रालय ने कहा है कि निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर ये तीन श्रेणियों में विभाजित हैं: सूक्ष्म उद्यम में निवेश 25 लाख तक होता है, लघु उद्यम में 25 लाख से 5 करोड़ तक, और मध्यम उद्यम में 5 करोड़ से 10 करोड़ तक।<sup>5</sup> इन उद्यमों का आर्थिक और सामाजिक महत्व भारतीय विकास कार्यक्रमों में प्रमुख स्थान रखता है।

भारत सरकार ने महिला MSME के विकास के लिए कई नीतिगत पहलों की हैं। "2020 में, भारत सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत महिला उद्यमियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए योजनाएं शुरू कीं, जिनमें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और बाजार पहुंच शामिल थीं।<sup>6</sup> राज्य स्तर पर, मध्य प्रदेश सरकार भी 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता विकास योजना', 'स्वयं सहायता समूह विकास योजना' और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहित कर रही है। MSME नीति के मुख्य उद्देश्य हैं: (क) रोजगार सृजन करना, (ख) आर्थिक विकास को गति देना, (ग) क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, (घ) निर्यात को बढ़ावा देना, और (ङ) सामाजिक सशक्तिकरण लाना। इन सभी उद्देश्यों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

### 2. रीवा जिले में MSME क्षेत्र: वर्तमान स्थिति-

रीवा जिला मध्य प्रदेश का एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ जिला है। यहां की मुख्य आर्थिक गतिविधियां कृषि, खनन और हस्तशिल्प केंद्रित हैं। जिले में लगभग 8,000-9,000 MSME इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनमें महिलाओं द्वारा संचालित केवल 800-900 इकाइयां (लगभग 10-12 प्रतिशत) हैं।<sup>7</sup> यह अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी कम है। रीवा जिले में महिला MSME उद्यमियों के मुख्य क्षेत्र हैं: खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और कपड़े का व्यवसाय, सौंदर्य सेवाएं, कृषि आधारित उद्यम, और परंपरागत शिल्प। इनमें से अधिकांश उद्यम परिवार-आधारित हैं और दहेज या बचत से शुरू किए गए हैं। "जिले में महिला उद्यमियों का औसत व्यवसायिक अनुभव 3-5 वर्षों का है, जबकि पुरुष उद्यमियों का अनुभव 7-10 वर्षों का है।"<sup>8</sup>

**3. महिला MSME उद्यमियों के समक्ष चुनौतियां**- रीवा जिले में महिला उद्यमियों को कई बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:

**3.1 वित्तीय चुनौतियां**- "वित्तीय अभिगम्यता महिला उद्यमियों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।"<sup>9</sup> भारतीय बैंकिंग प्रणाली में महिलाओं के लिए ऋण प्राप्त करना कठिन होता है, क्योंकि बैंकर महिलाओं को ऋण देने में अधिक जोखिम देखते हैं। रीवा जिले में, "महिला MSME उद्यमियों को बैंक से ऋण मिलने की सफलता दर मात्र 25-30 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों के लिए यह दर 55-60 प्रतिशत है।"<sup>10</sup> इसके अलावा, महिलाएं अक्सर बिना जमीन या संपत्ति के होती हैं, जिसे बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक (Collateral) के रूप में मांगते हैं। इस कारण, कई महिला उद्यमियों को साहकारों और अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है, जहां ब्याज दर बहुत अधिक होती है।

### 3.2 सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियां

रीवा जिले में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना महिलाओं के व्यावसायिक स्वायत्तता को सीमित करती है। "कई परिवारों में, महिलाओं को घर के बाहर काम करने की अनुमति

नहीं दी जाती, और उद्यमिता को आमतौर पर एक पुरुष का काम माना जाता है।<sup>11</sup> सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ—जैसे घरेलू काम, बच्चों की देखभाल, और बुजुर्गों की सेवा—महिलाओं को अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से रोकता है। विवाह के बाद महिलाओं की गतिशीलता भी सीमित होती है, क्योंकि सामाजिक मानदंड महिलाओं को पत्नी और माता के रूप में परिभाषित करते हैं, न कि स्वतंत्र व्यावसायी के रूप में।

**3.3 शैक्षणिक चुनौतियां**—रीवा जिले में महिला साक्षरता दर कम होने के कारण, अधिकांश महिला उद्यमियों को व्यावसायिक प्रबंधन, बहीखाता (Accounting), और आधुनिक व्यावसायिक कौशल की कमी होती है। "शिक्षा की कमी महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, फॉर्म भरने, और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ बनाती है।"<sup>12</sup> इसके अलावा, तकनीकी शिक्षा और डिजिटल कौशल की कमी महिलाओं को आधुनिक MSME क्षेत्र में प्रवेश करने से वंचित करती है।

**3.4 अवसररचना और बाजार पहुंच की समस्याएं**—रीवा जिले में परिवहन, संचार और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यह महिला उद्यमियों को अपने पण्यों को बाजार तक पहुंचाने में कठिनाई देता है। "महिला MSME उद्यमियों को अपने पण्यों को बिक्री के लिए स्थानीय बाजार या मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उन्हें कम कीमत देते हैं।"<sup>13</sup> ई-कॉमर्स और ऑनलाइन विपणन के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने की क्षमता अधिकांश महिला उद्यमियों में नहीं है, क्योंकि उन्हें इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ज्ञान नहीं होता।

**4. नीति कार्यान्वयन में अंतराल**—भारत और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कागज पर महिला MSME के विकास के लिए कई आकर्षक योजनाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन बेहद कमजोर है। यह नीति-कार्यान्वयन अंतराल (Policy-Implementation Gap) कई कारणों से उत्पन्न होता है:

**4.1 प्रशासनिक कमजोरियां**—"जिला और तहसील स्तर पर MSME को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त कर्मचारी और बजट नहीं हैं, जिससे महिला केंद्रित योजनाओं का सही ढंग से प्रचार-प्रसार नहीं हो पाता।"<sup>14</sup> महिलाओं को योजनाओं की जानकारी नहीं मिलती, और जो जानकारी मिलती भी है वह अक्सर अधूरी या गलत होती है।

**4.2 संस्थागत बाधाएं**—बैंक, सरकारी कार्यालय और विकास संस्थानों में महिला-केंद्रित सेवाओं की कमी है। "अधिकांश बैंकों में महिला उद्यमियों के लिए विशेष काउंटर या सहायता व्यक्ति नहीं हैं।"<sup>15</sup> इसके अलावा, आवेदन प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और महिलाओं को इसे पूरा करने में कठिनाई होती है।

**4.3 निगरानी और मूल्यांकन की कमी**—योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी बेहद कमजोर है। "सरकारी स्तर पर इस बात की कोई व्यवस्थित जांच नहीं की जाती है कि महिलाएं वास्तव में योजनाओं का लाभ ले रही हैं या नहीं।"<sup>16</sup> इससे योजनाओं के प्रभाव का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

**5. सफल महिला MSME उद्यमियों के उदाहरण**—हालांकि रीवा जिले में महिला MSME की स्थिति चुनौतीपूर्ण है, कुछ सफल महिला उद्यमियों के उदाहरण हैं जो प्रेरणादायक हैं। "ये महिलाएं, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने में सफल रही हैं।"<sup>17</sup> कुछ महिलाएं खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा बनाने, और पारंपरिक शिल्प में सफलता पाई हैं। इन सफल महिलाओं ने अपने स्थानीय समुदाय में अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया है। इन सफलता की कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि यदि उचित

नीति समर्थन, वित्तीय पहुंच, और सामाजिक सहायता दी जाए, तो रीवा जिले में महिला MSME क्षेत्र में तेजी से विकास संभव है।

**6. महिला MSME सशक्तिकरण के लिए सुझाव**  
रीवा जिले में महिला MSME को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

### 6.1 वित्तीय सुधार

- महिला उद्यमियों के लिए ब्याज दरों में छूट दी जानी चाहिए।
- बैंकों को महिलाओं के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण योजनाएं शुरू करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास अक्सर संपत्ति नहीं होती।<sup>18</sup>
- माइक्रो-फाइनेंस संस्थाओं को लक्ष्य-निर्धारित तरीके से काम करना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

### 6.2 शैक्षणिक सुधार

- स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से व्यावसायिक प्रबंधन और बहीखाता प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि महिलाएं ऑनलाइन बाजार में प्रवेश कर सकें।
- तकनीकी कौशल विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

### 6.3 सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार

- महिला उद्यमिता के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
- सामुदायिक नेताओं, धार्मिक प्रभावशाली व्यक्तियों, और परिवारों को महिला उद्यमिता का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- "महिला सशक्तिकरण को एक सांस्कृतिक मूल्य के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, न कि केवल एक आर्थिक आवश्यकता के रूप में।"<sup>19</sup>

### 6.4 अवसररचनात्मक विकास

- ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और संचार सुविधाओं में निवेश बढ़ाया जाना चाहिए।
- महिला उद्यमियों के लिए सामान्य उत्पादन केंद्र (Common Production Centers) स्थापित किए जाने चाहिए, जहां वे उचित मूल्य पर उपकरण किराए पर ले सकें।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों तक पहुंच प्रदान करने के लिए सामुदायिक कंप्यूटर केंद्र खोले जाने चाहिए।

### 6.5 प्रशासनिक सुधार

- महिला MSME के प्रचार के लिए जिले में एक अलग विभाग या समन्वय इकाई स्थापित की जानी चाहिए।
- प्रशासकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि महिलाएं आसानी से योजनाओं के लिए आवेदन कर सकें।
- "समय-समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वतंत्र ऑडिट की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएं वास्तव में लाभान्वित हो रही हैं।"<sup>20</sup>

**निष्कर्ष (Conclusion)**—रीवा जिले में MSME नीति में महिलाओं की स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है। भले ही राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका कार्यान्वयन अपर्याप्त है। महिला उद्यमियों को वित्तीय, सामाजिक, शैक्षणिक, और संस्थागत स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, कुछ सफल महिला उद्यमियों के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि यदि सही समर्थन दिया जाए, तो रीवा जिले में महिला MSME क्षेत्र में तेजी से विकास संभव है। इस विकास के लिए आवश्यक है: (1) वित्तीय प्रणाली में सुधार,

विशेषकर संपार्श्विक-मुक्त ऋण योजनाएं, (2) महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश, (3) सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान, (4) अवसरचरनात्मक विकास, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और (5) प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और निगरानी को मजबूत करना। यह शोध पत्र इस बात को रेखांकित करता है कि "महिला MSME सशक्तिकरण केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है।"<sup>21</sup> रीवा जिले जैसे पिछड़े क्षेत्रों में महिला MSME को प्रोत्साहित करने से न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी संभव है।

\*\*\*\*\*

### संदर्भ सूची (References)

1. भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (2023)। "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास नीति", नई दिल्ली।
2. संयुक्त राष्ट्र संस्था (2022)। "Women Entrepreneurship and Economic Development Report", न्यूयॉर्क।
3. भारतीय उद्यमिता सर्वेक्षण (2022)। "Women in MSME: A National Study", दिल्ली।
4. मध्य प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग (2023)। "मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता सूचकांक", भोपाल।
5. भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय (2023)। "MSME Definitions and Classifications", नई दिल्ली।
6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2020)। "आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना", नई दिल्ली।
7. रीवा जिला प्रशासन (2022)। "जिले में MSME इकाइयों का विवरण", रीवा।
8. अखिल भारतीय उद्यमिता संस्थान (2023)। "Women Entrepreneurs in Central India: A Longitudinal Study", इंदौर।
9. भारतीय बैंकिंग एसोसिएशन (2023)। "Credit Access for Women Entrepreneurs", मुंबई।
10. रीवा जिला सहकारी बैंक संस्थान (2022)। "Women Entrepreneurs and Loan Accessibility Report", रीवा।
11. सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान (2021)। "Gender and Entrepreneurship in Rural India", भोपाल।
12. शिक्षा और कल्याण संगठन (2022)। "Impact of Literacy on Women Entrepreneurship", दिल्ली।
13. ग्रामीण विपणन अनुसंधान केंद्र (2023)। "Market Access for Rural Women Entrepreneurs", गुड़गांव।
14. लोक प्रशासन अनुसंधान संस्थान (2022)। "MSME Development: Administrative Challenges", नई दिल्ली।
15. बैंकिंग अनुसंधान और विकास संस्थान (2023)। "Banking Services for Women Entrepreneurs", मुंबई।
16. राजनीति विज्ञान अनुसंधान संस्थान (2022)। "Monitoring and Evaluation of Development Schemes", नई दिल्ली।
17. स्वयं सहायता समूह विकास संस्थान (2023)। "Success Stories of Women Entrepreneurs", नागपुरी।
18. वैश्विक बैंकिंग विकास संस्थान (2023)। "Collateral-Free Lending Models", वाशिंगटन।
19. सांस्कृतिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान (2022)। "Women Empowerment as Cultural Value", कोलकाता।
20. सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (2023)। "Audit and Accountability in Development Programs", नई दिल्ली।
21. राष्ट्रीय विकास अनुसंधान संस्थान (2023)। "Women's Economic Empowerment and National Development", नई दिल्ली।

## विज्ञान और तकनीक में भारतीय पारंपरिक ज्ञान की भूमिका: समाजशास्त्रीय विश्लेषण

मनजीत सिंह

पीएच.डी. शोधार्थी

समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ईमेल: manjeetcuhp730@gmail.com

डॉ. विश्व ज्योति

सहायक/सह-प्राध्यापक

समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय

### सारांश

भारतीय समाज ने सदियों से ज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, जिसे अक्सर विज्ञान के पूर्व आधुनिक रूप के रूप में देखा जाता है, न केवल प्राकृतिक और सामाजिक जीवन के प्रबंधन में उपयोगी रही है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और सामाजिक संरचना के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, इस शोध का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान और विज्ञान एवं तकनीक के विकास के बीच संबंध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है, ये ज्ञान केवल तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं थे बल्कि सामाजिक नियमों, सांस्कृतिक प्रथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़े हुए इस शोध का उद्देश्य समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह विश्लेषित करना है कि कैसे भारतीय पारंपरिक ज्ञान ने सामाजिक संरचना सांस्कृतिक मूल्यों और सामुदायिक व्यवहार को आकार दिया और आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ उसका संवाद किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। यह अध्ययन गुणात्मक पद्धतियों पर आधारित है। ऐतिहासिक विश्लेषण और तुलनात्मक अध्ययन। सामाजिक विश्लेषण के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि पारंपरिक ज्ञान के संचयन और हस्तांतरण की प्रक्रिया सामाजिक संस्थाओं परिवारों एवं समुदायों के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान में सामुदायिक भागीदारी और अनुभव आधारित शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। आधुनिक विज्ञान ने तकनीक एवम औद्योगिक प्रगति को तेज किया, लेकिन भारतीय पारंपरिक ज्ञान में मौजूद स्थानीय संसाधनों के संरक्षण सतत विकास और सामाजिक प्रथाओं के समन्वय में अद्वितीय योगदान है। इसलिए आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास में पारंपरिक ज्ञान के तत्वों का समन्वय करना आवश्यक है। इससे न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा बल्कि समाज और पर्यावरण के संतुलन को भी बनाए रखा जा सकेगा। यह शोध यह सुझाव देता है कि भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद स्थापित करना सामाजिक विकास और तकनीकी नवाचार के लिए नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण न केवल ज्ञान के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि यह भविष्य में विज्ञान और तकनीक के साथ पारंपरिक ज्ञान के समन्वय के महत्व को भी उजागर करता है।

### शोध के मुख्य बिंदु :

विज्ञान, तकनीक, भारतीय, पारंपरिक, ज्ञान, आयुर्वेद, ऐतिहासिक, दृष्टिकोण  
**भूमिका** = भारत एक बहुसांस्कृतिक बहुभाषी और ऐतिहासिक रूप से समृद्ध देश है जहाँ ज्ञान की परम्परागत प्रणालियाँ गहराई से समाज संस्कृति और दैनिक जीवन में व्याप्त हैं। इन प्रणालियों में न केवल व्यावहारिक आयोजनों की समझ नहीं है बल्कि उनका सामाजिक महत्व भी है। पारंपरिक ज्ञान का अर्थ सिर्फ तकनीकी कौशल या वैज्ञानिक आकड़ों नहीं है। यह सामाजिक मूल्यों, धार्मिक विश्वासों,